(d) Measures for improving supply position include expediting the completion of ongoing projects, renovation and mdernisation of existing power stations, reduction in transmission and distribution losses, efficient load management and energy conservation.

कोयला-उत्पादन के बढ़ाकर दर्शाये गए आंकड़े

1434. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि० ने कोयला उत्पादन के आंकड़े बढ़ाकर दर्शाये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोल इंडिया लि० के निर्देशक के निर्देश से भारत कोकिंग कोल लि० और सेंट्रल कोल्ड फील्ड लि० द्वारा कोयला उत्पादन के आंकड़े बढ़ाकर दर्शाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार बढ़े आंकड़े दर्शाये जाने के बारे में जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति कार्रवाई करने का भी विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोयला कंपनियों के पास प्रतिमाह प्रत्येक खान द्वारा उत्पादित किए गए कोयले के भूमिगत भंडारों को नापने के लिए एक वेल्यूमेट्रिक प्रणाली है । इस आशय की प्रमाणिकता समय-समय पर कोल इंडिया लि० तथा सहायक कोयला कंपनियों के कारपोरेट कार्यालयों द्वारा नियुक्त सवेक्षण दलों द्वारा की जाती है । अत: इस संबंध में उत्पादन की गलत सूचना प्रस्तुत करने की बहुत कम संभावना है, किन्तु किसी वस्तु की वास्तविक नापतोल की तुलना में वैल्यूमेट्रिक प्रणाली से की गई नाप में सदैव कुछ अंतर रह जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऊर्जा मंत्रालय की परामर्शदाता समिति की हुई 30 जून 1988 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सरकार परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति गठित की जोकि निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ कोयले की उठाई गिरी, चोरी तथा कोयले के भंडारों की कमी के संबंध में आरोपित शिकायतों को जांच करेगी :—

(1) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों की कोयले की सूचियो तथा उस की भंडारण नीति की जांच, और

(2) कोल इंडिया लि० द्वारा स्थापित की गई कोलियरियों/स्टाकयार्डों से कोयले का प्रेषण तथा प्राप्ति की जांच ।

इस संबंध में गठित उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बी०सी०सी०एल० में कोयला-उत्पादन

1435. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी०सी०सी० एल० का प्रबंधमंडल अपने प्रतिवेदनों और समाचारपत्रों में कोयला उत्पादन संबंधी आंकड़े हमेशा बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करता है ;

(ख) क्या सरकार इन मिथ्या आंकडों की एकपक्ष जांच कराने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या ऐसा दिल्ली में सहकारी अधिकारियों की मिली भगत से किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं । अन्य कोयला कंपनियों की तरह भारत कोकिंग कोल लि० में भी प्रतिमाह प्रत्येक खान द्वारा किए गए कोयले के उत्पादन के भी विगत भंडारों को नापने के लिए एक वैल्युमेट्रिक प्रणाली विद्यमान है । कोयले का उत्पादन तथा उसके भंडारों को कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के मुख्यालय द्वारा नियुक्त किए गए सर्वेक्षण दल समय-समय पर अधिप्रमाणित करते हैं । अत: इस संबंध में उत्पादन को आंकड़ों को गलत प्रस्तुत करने की बहुत कम संभावना है।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० के बारे में विशेष रूप से कोई जांच किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। किन्तु संसदीय कार्य मंत्रालय की 30 अगस्त 1988 की अधिसूचना संख्या एफ० 8-7 ( ) /88-सी० बी० के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप-समिति गठित

की गई जो कि निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ कोयले की उठाईगिरी, चोरी, तथा कोयले के भंडारों की कमी की आरोपित शिकायतों की जांच करेगी :—

(i) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों की कोयले की सूचियों तथा उसकी भंडारण नीति की जांच ; और

(ii) कोल इंडिया लि० द्वारा स्थापित की गई कोलियारियो /स्टाकयार्डों से कोयले का प्रेषण तथा प्राप्ति की जांच ।

इस संबंध में गठित उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

Providing Electricity to Institutional Area Behind Qutab Hotel

1436. SHRI RAM AWADESH SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that low tension power lines have not been provided so far to the Institutional Area behind Qutab Hotel even after a lapse of 3-4 years causing undue and continued hardship to the occupants due to temporary connections; and

(b) whether DESU will expedite the laying of low tension power lines and provide permanent connectiions?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) and (b) According to Delhi Electricity Supply Undertaking, the electricity system established in the Institutional Area of a few years back needs augmentation for meeting the additional load requirement in view of the subsequent development of the area. Consequently, an electrification scheme was prepared by DESU in consultation with the D.D.A., who were requested on 21.11.1988 to make payment of their share amounting to Rs. 55,54,880|-. DESU can take further action in the matter on receipt of the payment from the DDA.

Fire in DESU workshop

1437. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report which appeared in the Hindustan Times of the 7th April, 1989 to the effect that a major fire broke out in the transformer repairing workshop of the Delhi Electric Supply Undertaking at Phase-2 of Okhla Industrial area on 6th April, 1989;

(b) if so, what were the causes of the fire; and

(c) the number of persons injured and killed and the estimated loss of property as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) According to DESU, it is suspected that an L.T. cable feeding the workshop was damaged and the sparks from the cable ignited the oil in the oil pipes.

(c) According to DESU, no one was killed or seriously injured in the said fire. The estimated loss of DESU property is around Rs. 9 lakhs.

Separate Telecommunication Division for Darrang district

1438. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for setting up of a separate Telecommunication Division for Darrang district at Mangaldai delinking the district from the present division at Nalbari; and